प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-20825/प्रो०अनु०(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/15/2026(बै०दि० 20.04.2026) दिनांक-26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, जो ग्राम-कन्धारतला, राहमऊ नौबस्ता, थाना-माल, जनपद-लखनऊ का निवासी है। दहेज में मोटर साइकिल व पंखे की मांग पूरी न होने पर दिनांक-13.05.2012 को अभियुक्त द्वारा अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-440/2013, भा०द०वि० की धारा-304बी, 498ए व धारा-4 डी०पी० एक्ट में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) कोर्ट सं0-06 लखनऊ के आदेश दिनांक-05.08.2019 द्वारा 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.11.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 02 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 03 माह, 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज में मोटर साइकिल व पंखे की मांग पूरी न होने पर दिनांक-13.05.2012, को अभियुक्त द्वारा अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनील कुमार पुत्र श्री बाबूलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार (बन्दी संख्या-762/2019) पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी जनपद-लखनऊ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1299/2026/997(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1299/2026/997/22-2-2026-17(635)/2026

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, जो ग्राम-कन्धारतला, राहमऊ नौबस्ता, थाना-माल, जनपद-लखनऊ का निवासी है। दहेज में मोटर साइकिल व पंखे की मांग पूरी न होने पर दिनांक-13.05.2012 को अभियुक्त द्वारा अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-440/2013, भा०द०वि० की धारा-304बी, 498ए व धारा-4 डी०पी० एक्ट में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) कोर्ट सं0-06 लखनऊ के आदेश दिनांक-05.08.2019 द्वारा 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.11.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 02 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 03 माह, 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज में मोटर साइकिल व पंखे की मांग पूरी न होने पर दिनांक-13.05.2012, को अभियुक्त द्वारा अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनील कुमार पुत्र श्री बाबूलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।